

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 46

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 3 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

बिहार की दो मानव निर्मित आद्रभूमियों नागी और नकटी को रामसर स्थल के रूप में दी गई मान्यता

नई दिल्ली। देश भर में जारी भीषण गर्मी और सूखते जल निकायों के बीच, बिहार से अच्छी खबर सामने आई है, जहां नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमियों (वेटलैंड्स) के रूप में मान्यता दे दी गई है।

ये मानव निर्मित आद्रभूमियां अनगिनत वनस्पतियों के साथ-साथ कई तरह के जीवों, विशेष रूप से पक्षियों के प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। गौरतलब है कि यह दोनों ही आद्रभूमियां बिहार के जमुई में स्थित हैं। इनके शामिल होने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड है जो 4,230 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेगूसराय जिले में मौजूद कंवर झील को बिहार की पहली रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। हालांकि डाउन टू अर्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रामसर साइट की हालत यह है कि वो कभी भी सूख सकती है और वहां खेती शुरू की जा सकती है। बता दें कि रामसर कन्वेंशन, आद्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसपर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। बिहार के मुख्य वन्यजीव वार्डन पीके गुप्ता ने दो आद्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में मान्यता दिए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने डाउन टू अर्थ से हुई बातचीत में कहा कि, हमें इसकी उम्मीद थी। यह हमें राज्य में अन्य आद्रभूमियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। इस खबर का देश भर के पर्यावरणविदों और पक्षी विशेषज्ञों ने भी स्वागत किया है। बिहार के पक्षी विशेषज्ञ और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य अरविंद मिश्रा ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि, मुझे बेहद खुशी है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को भारत में 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। मैं इस मान्यता के लिए बिहार के



वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के शीर्ष अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। मिश्रा का यह भी कहना है कि यह दोनों अभयारण्य सर्दियों में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिनमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, करीब दो साल पहले विभाग ने बिहार में पांच आद्रभूमियों के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया था, जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को भेजा जाना था। इनमें दरभंगा में कुशेश्वर अस्थान, वैशाली में ताल बरैला, कटिहार में गोगाबील, जमुई में नागी और नकटी बांध शामिल थे।

इनमें जहां नागी पक्षी अभयारण्य 791 हेक्टेयर में फैला है, वहीं नकटी पक्षी अभयारण्य का विस्तार 333 हेक्टेयर में है। रामसर साइट इन्फॉर्मेशन सर्विस वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ये दोनों अभयारण्य मानव निर्मित आद्रभूमि हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण की मदद से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। यह भी कहा गया है कि, बांध निर्माण के बाद से, आद्रभूमि और इसके आस-पास के क्षेत्रों ने पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृपों और उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है। इन प्रजातियों में भारत के लुप्तप्राय महान हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) संकटग्रस्त देशी कैटफिश (वालगो अट्टू) जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इन आद्रभूमियों का जलग्रहण क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वन में है, जो पहाड़ियों से घिरे हैं। 1984 में, इस आद्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि यह कई प्रवासी प्रजातियों के लिए सर्दियों के आवास के रूप में बेहद मायने रखती है। सर्दियों के दौरान यहां 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं, जिनमें इंडो-गंगा के मैदान पर लाल-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्टा रूफिना) का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। स्थानीय समुदायों की पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ यह अभयारण्य पक्षियों को देखने की भी एक लोकप्रिय जगह है। 2023 एशियाई जलपक्षी जनगणना (एडब्ल्यूसी) के मुताबिक, नकटी पक्षी अभयारण्य में सबसे अधिक 7,844 पक्षी दर्ज किए गए, इसके बाद नागी पक्षी अभयारण्य में इन पक्षियों की संख्या 6,938 दर्ज की गई थी।

महाकुंभ नजदीक लेकिन प्रयागराज की गंगा-यमुना में बह रहा सीवेज

इस बार कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी, 2025 में होगा, लेकिन हैरानी भरा यह है कि गंगा और यमुना में सीवेज बह रहा है। फिलहाल गंगा का पानी श्रद्धालुओं के आचमन और नहाने लायक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ गंगा-यमुना में डुबकी लगाते हैं बल्कि वह जल का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सीवेज की रोकथाम को लेकर समयबद्ध तरीके से तेज प्रयास करने चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कुल 81 नालों के जरिए 289.97 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज निकलता है जिसमें से महज 178.31 एमएलडी सीवेज ही मौजूदा 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सीवेज नेटवर्क के जरिए पहुंचता है, जिसका सीधा अर्थ है कि 128.28 एमएलडी सीवेज का उपचार नहीं किया जा रहा है।

एनजीटी चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जुलाई, 2024 को एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आगामी महाकुंभ को लेकर कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया जा रहा है। 81 में से 44 नाल ऐसे हैं जो अभी तक अनछुए (अनटैप) हैं और जिनके जरिए 73.80 एमएलडी गैर शोधित सीवेज सीधा गंगा में गिर रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ने कहा कि नवंबर 2024 तक 44 में



से 17 नालों को टैप किया जाएगा और उन्हें एसटीपी से जोड़ दिया जाएगा, जिससे 11.61 एमएलडी सीवेज की रोकथाम हो जाएगी। इसके अलावा 44 नालों के सीवेज उपचार में कमी को पूरा करने के लिए कुल 183 एमएलडी क्षमता वाले तीन एसटीपी बनाए जा रहे हैं। इन तीनों एसटीपी की क्षमता 90, 43 और 50 एमएलडी है। उत्तर प्रदेश सरकार की दलील से पीठ संतुष्ट नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 90 और 50 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी के लिए अभी तक निविदा प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। वहीं, 43 एमएलडी वाले एसटीपी का काम ही 19 मार्च, 2024 से शुरू हुआ है। पीठ ने कहा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट से कई कमियां और संदेह उजागर हो रहा है, मसलन प्रयागराज में हर दिन नालों और सीवेज नेटवर्क के जरिए 468.28 एमएलडी सीवेज पैदा होता है। इसमें से 73.80 एमएलडी 44 अनछुए नालों के जरिए गंगा में गिर रहा है, बाकी 394.48 एमएलडी सीवेज को 340 एमएलडी की क्षमता वाले 10 एसटीपी में भेजा रहा है, ऐसे में इस स्पष्टता की जरूरत है कि क्षमता से अधिक आने वाले सीवेज का मानकों के आधार पर उपचार कैसे किया जा रहा है? पीठ ने कहा कि यह भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि 1,66,456 घरों को अभी सीवेज नेटवर्क से जोड़ा जाना है, ऐसे में सीवेज को उपचार के लिए मौजूदा एसटीपी पर या फिर प्रस्तावित एसटीपी पर भेजा जाएगा? पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीवेज डिस्चार्ज की रोकथाम को लेकर उचित कदम उठाने के साथ प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त, 2024 के लिए तय की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गंगा-यमुना में सीवेज डिस्चार्ज न सिर्फ पूरी तरह से रुकना चाहिए बल्कि नदी के पानी की गुणवत्ता पीने योग्य बनाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि नदी के पानी की गुणवत्ता को स्नानघाट पर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए डिस्पले में दिखाया और सूचित भी किया जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम ने खरीदा 266 लाख टन गेहूं, पिछले साल से 4 लाख अधिक

भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले साल के 262 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है।

रबी विपणन सीजन के तहत गेहूं की खरीद आम तौर पर हर साल 1 अप्रैल को शुरू होती है। हालांकि इस साल अधिकांश राज्यों में लगभग एक पखवाड़े पहले खरीद शुरू हो गई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञप्ति में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपनी गेहूं खरीद की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 2.20 लाख टन की तुलना में इस साल 9.31 लाख टन की खरीद की है, जबकि राजस्थान ने पिछले सीजन के 4.38 लाख टन के मुकाबले इस साल 12.06 लाख टन खरीद की है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि धान की वर्तमान खरीद ने केंद्रीय पूल चावल के स्टॉक को 490 लाख टन से अधिक कर दिया है, जिसमें मिलिंग के बाद प्राप्त होने वाला 160 लाख चावल भी शामिल है। चावल की वार्षिक आवश्यकता लगभग 400 लाख टन है, जबकि 1 जुलाई के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित बफर मानदंड 135 लाख है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा के तहत चल रही योजनाओं के लिए सालाना लगभग 184 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है।



18 महीने पहले ही पता लग जाएगा अल नीनो का, चरम मौसम संबंधी खतरों से बचने में अहम

नई दिल्ली(एजेन्सी) एल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) भारत समेत पूरे एशिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में हवाओं, मौसम और समुद्र के तापमान में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। यह सूखे, बाढ़, फसलों की हानि और भोजन की कमी का कारण बन सकता है।

हम सब ने 2023-2024 में एल नीनो की घटना महसूस की, जिसने दुनिया भर के मौसम, जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर भारी असर डाला। मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय के महासागर और पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल (एसओईएसटी) के शोधकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक नया मॉडल विकसित किया है। इसकी मदद से वे 18 महीने पहले तक ईएनएसओ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे पारंपरिक जलवायु मॉडल पूर्वानुमान में काफी सुधार हो सकता है। शोधकर्ताओं के महासागर और वायुमंडल को लेकर सटीक पूर्वानुमान लगाने वाले निष्कर्ष नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, नया मॉडल जिसे उन्होंने विस्तारित नॉनलीनियर रिचार्ज ऑसिलेटर (एक्सआरओ) मॉडल नाम दिया गया है। यह एक साल से अधिक समय पहले ईएनएसओ घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में भारी सुधार कर सकता है, जो दुनिया भर के लवायु मॉडल से बेहतर है और सबसे कुशल एआई पूर्वानुमानों के बराबर है। शोध के मुताबिक, यह मॉडल ईएनएसओ के मूलभूत भौतिकी और वैश्विक महासागरों में अन्य जलवायु पैटर्न के साथ ईएनएसओ की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावी ढंग से शामिल करता है जो मौसम दर मौसम बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक दशकों से ईएनएसओ के वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को देखते हुए इसके पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पारंपरिक तरीके से पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल एक वर्ष से अधिक समय के साथ ईएनएसओ का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगाने में संघर्ष करते रहे हैं।

एआई नए पूर्वानुमान की सटीकता में भारी सुधार करने में मदद करता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में हाल ही में हुई प्रगति ने इन सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे 16 से 18 महीने पहले तक सटीक पूर्वानुमान हासिल हुए हैं। शोध के मुताबिक, एआई मॉडल में पूर्वानुमान के स्रोत की जांच पड़ताल करने में सक्षम न होने के कारण कम विश्वास होता है कि ये भविष्य की



घटनाओं के लिए सफल होंगे क्योंकि पृथ्वी गर्म होती जा रही है, जिससे महासागरों और वायुमंडल में धाराएं बदल रही हैं। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से बताया, एआई मॉडल की प्रकृति के विपरीत, हमारा एक्सआरओ मॉडल भूमध्यरेखीय प्रशांत रिचार्ज-डिस्चार्ज भौतिकी के तंत्र और उष्णकटिबंधीय प्रशांत के बाहर अन्य जलवायु पैटर्न के साथ इसकी आंतरिक क्रियाओं के बारे में एक पारदर्शी नजरिया प्रदान करता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय प्रशांत, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर और अटलांटिक की शुरुआती अवस्थाएं अलग-अलग मौसमों में ईएनएसओ के पूर्वानुमान को बढ़ाती हैं। पहली बार, हम ईएनएसओ के पूर्वानुमान पर उनके प्रभाव को मजबूती से मापने में सक्षम हैं, इस प्रकार ईएनएसओ भौतिकी और इसके पूर्वानुमान के स्रोतों के बारे में जानकारी बढ़ जाती है।

जलवायु मॉडल की कमियों में सुधार शोध के अनुसार, इसके निष्कर्ष जलवायु मॉडल की नवीनतम पीढ़ी में कमियों की भी पहचान करते हैं, जिसके कारण ईएनएसओ का सटीक पूर्वानुमान लगाने में वे विफल हो जाते हैं। ईएनएसओ पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए, जलवायु मॉडल को ईएनएसओ के मुख्य भौतिकी को सही ढंग से समझना चाहिए और इसके अतिरिक्त, वैश्विक महासागरों में अन्य जलवायु पैटर्न के तीन मिश्रित पहलुओं को भी समझना चाहिए- ईएनएसओ पूर्वानुमान शुरू होने पर इनमें से प्रत्येक जलवायु पैटर्न की स्थिति का सटीक जानकारी, इनमें से प्रत्येक जलवायु पैटर्न की सही मौसमी रूप से बदलती %महासागर स्मृति% और इन अन्य जलवायु पैटर्न में से प्रत्येक अलग-अलग मौसमों में ईएनएसओ को कैसे प्रभावित करता है, इसका सही तरीका। शोध के मुताबिक, अल नीनो के अतिरिक्त, नया एक्सआरओ मॉडल उष्णकटिबंधीय हिंद और अटलांटिक महासागरों में अन्य जलवायु में होने वाले बदलाव के पूर्वानुमान में भी सुधार करता है, जैसे कि हिंद महासागर डिपोल, जो अल नीनो के प्रभावों से परे स्थानीय और वैश्विक मौसम पैटर्न को भारी तौर पर बदल सकता है।

भविष्य में और सटीक होगा पूर्वानुमान

शोध में कहा गया है कि यह ईएनएसओ की अधिक सटीक और लंबी अवधि के पूर्वानुमान और वैश्विक जलवायु मॉडल में सुधार का अवसर प्रदान करता है। हालांकि ईएनएसओ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में होती है, लेकिन अब हम इसे केवल उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की समस्या के रूप में नहीं सोच सकते, चाहे मॉडलिंग और पूर्वानुमान के जरिए से या अवलोकन के नजरिए से। वैश्विक उष्णकटिबंधीय और उच्च अक्षांश मौसमी जलवायु पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए अहम हैं। मॉडल की कमियों का पता लगाकर, जलवायु पैटर्न की आंतरिक क्रियाओं को समझ कर, हम अपने वैश्विक जलवायु मॉडल को काफी हद तक बदल सकते हैं। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि, इससे वैश्विक जलवायु मॉडल की अगली पीढ़ी के लिए इन निष्कर्षों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जलवायु में बदलाव के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने के हमारे नजरिए में सुधार होगा। ऐसी प्रगति सामाजिक तैयारियों और जलवायु-संबंधी खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।



अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर्यावरण संरक्षण का महत्व

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य प्लास्टिक बैगों के उपयोग के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह एक ग्लोबल पहल है जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करती है। प्लास्टिक से इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है कि मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। नदियां नाला बन चुकीं और विलुप्त होने का गार पर है। प्लास्टिक की उत्पत्ति और उसके प्रयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं।

जागरूकता फैलाना

अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का आयोजन पहली बार 2009 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से प्लास्टिक बैगों के उपयोग को रोकने की एक पहल है।

नकारात्मक प्रभावों को समझना

इस दिन को मनाने से लोगों में जागरूकता बढ़ती है और वे इसके नकारात्मक प्रभावों को समझते हैं। प्लास्टिक बैगों का उपयोग कम करने से पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक परिणाम देखने की संभावना होती है जैसे कि समुद्रों में प्लास्टिक की मात्रा कम होना। इस प्रकार, हम सभी मिलकर प्रदूषण रहित पर्यावरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और अपनी पूरी तरह से प्लास्टिक बैगों के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर सड़क सफाई अभियान और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव भी आम तौर पर इस दिन को मनाया जाता है।



सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति- चुनौतियां और अवसर

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 2030 के एजेंडे के एक हिस्से, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में छह वर्ष से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में इसके 17 लक्ष्यों और 169 संबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को अभी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। इन वैश्विक लक्ष्यों को 2015 में अपनाया गया था और ये गरीबी उन्मूलन, लैंगिक न्याय हासिल करने, पृथ्वी को सुरक्षित रखने तथा सभी के वास्ते शांति और समृद्धि हासिल करने की दिशा में कदम उठाने के लिए एक सार्वजनिक आह्वान हैं। इस संदर्भ में हाल में जारी भारत में एसडीजी की प्रगति रिपोर्ट डेटा आधारित प्रमाण पेश करती है। यह बताती है कि एसडीजी और उससे जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में भारत की प्रगति मिलीजुली रही है।

एसडीजी 1 के तहत भारत ने हाल के वर्षों में गरीबी उन्मूलन के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में 9.89 फीसदी की कमी आई और यह 2015-16 से 2019-21 के बीच घटकर 14.96 फीसदी रह गई। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 2022-23 में यह और गिरकर 11.28 फीसदी रह जाएगी। भविष्य में गरीबी के स्तर में और कमी लाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी तथा लोगों की खर्च योग्य आय बढ़ानी होगी। अन्य क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार के निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ओर जहां मांओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तथा कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, वहीं 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में खून की कमी के मामलों में इजाफा हुआ है। एसडीजी 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामलों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकन, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण में भागीदारी दर, दिव्यांग बच्चों के नामांकन, शिक्षक-छात्र अनुपात और स्कूल बुनियादी ढांचे के मामले में 2015-16 से अब तक काफी सुधार हुआ है। बहरहाल, कक्षा पांचवीं और आठवीं की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों की तादाद महामारी के पहले के स्तर से नीचे आ गई है। यह बताता है कि महामारी ने अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है। इसके अलावा महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ने के साथ ही वेतन की असमानता, दहेज के मामले और अपराधों की तादाद भी बढ़ी है। इनमें महिलाओं पर यौन अपराध शामिल हैं। ये कारक बताते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के क्षेत्र में सरकारी व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। बहरहाल, रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कुल सरकारी व्यय में अनिवार्य सेवाओं पर होने वाला व्यय महामारी के पहले के स्तरों से कम हुआ है। टिकाऊ और कार्बन निरपेक्ष वृद्धि की तलाश में भारत ने ग्लासगो में 2021 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में यह लक्ष्य तय किया था कि 2070 तक उसे 'नेट जीरो' उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना होगा। यह रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ी हिस्सेदारी और बेहतर औद्योगिक पर्यावरण अनुपालन के साथ सकारात्मक संकेत देती है। बहरहाल, प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन खपत में इजाफा और वन क्षेत्र में इजाफा नहीं होने ने इस प्रगति का प्रतिकार करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवंटित सरकारी व्यय के अनुपात में भी मामूली सुधार हुआ है। यह 2015-16 से 2022-23 के बीच केवल 0.3 फीसदी बढ़ा है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार को और कदम उठाने की आवश्यकता है। शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों से संबंधित एसडीजी 16 शांति, प्रभावी शासन और पारदर्शी न्याय व्यवस्था चाहता है। इसके विपरीत रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों पर अपराध हर वर्ष बढ़ रहे हैं। भारत प्रति एक लाख आबादी पर 1.93 अदालतों और 1.53 न्यायाधीशों के साथ वैश्विक मानकों से बहुत पीछे है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों के जवाब देने का प्रतिशत कम हुआ है। कुल मिलाकर जहां भारत स्वस्थ गति से बढ़ रहा है, वहीं वृद्धि के लाभ आबादी के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आर्थिक वृद्धि कुछ जगहों पर केंद्रित होगी तो इससे लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर असर होगा। बेहतर होगा कि सरकार आने वाले वर्षों में तय लक्ष्य पाने के लिए उन क्षेत्रों पर जोर दे जहां हम अभी पीछे हैं।